

एमएसएमई लोन की गारंटी लेने में यूपी देश में शीर्ष पर

18.26 लाख इकाइयों के साथ गुजरात व महाराष्ट्र से आगे निकला

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। देश भर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सुरक्षित कर्ज देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत बैंकों द्वारा दी गई गारंटी राशि 31 दिसंबर 2025 तक करीब 12.38 लाख करोड़ तक पहुंच गई है।

यह रकम उस लोन का बीमा है, जिनमें डिफॉल्ट होने पर बैंकों को सुरक्षा मिलती है। इसमें उत्तर प्रदेश ने 18.26 लाख छोटी इकाइयों की गारंटी ली है, जो महाराष्ट्र और गुजरात की संख्या को मिलाने के बाद भी ज्यादा है। इस तरह राज्य सरकार के करीब 1.28 लाख करोड़ रुपये की गारंटी ली है।

एमएसएमई इकाइयों को लेकर बैंकों की दिसंबर तक की संयुक्त रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। सीजीटीएमएसई योजना में औद्योगिक रूप से मजबूत राज्यों का दबदबा है। महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश गारंटी की संख्या में देश में शीर्ष

गारंटी लेने वाले देश के टॉप 5 राज्य



रैंक	राज्य	गारंटी संख्या
1	उत्तर प्रदेश	18,26,848
2	महाराष्ट्र	11,16,645
3	तमिलनाडु	10,15,248
4	कर्नाटक	9,49,311
5	गुजरात	6,18,423

इन शहरों में बैंक लोन हैं सर्वाधिक सुरक्षित

रैंक	जिला	गारंटी संख्या	बीमित राशि (करोड़ रुपये में)
1	लखनऊ	19,347	4,130
2	गौतमबुद्धनगर	8,611	2,595
3	गाजियाबाद	9,730	2,102
4	कानपुर नगर	13,104	1,792
5	वाराणसी	14,296	1,228
6	आगरा	10,426	1,222
7	प्रयागराज	10,967	978
8	गोरखपुर	9,531	921
9	मेरठ	7,081	874
10	बरेली	8,103	851

पर रहते हुए कुल राशि में भी टॉप-5 में शामिल है। सीजीटीएमएसई के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बीमित राशि

वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। यहां 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज सुरक्षित है।